

DIRECTIVE PRINCIPLES OF STATE POLICY (DPSP)

Varun Awasthi (GS Guru)

Directive Principles of State Policy (DPSP)

- Part IV ✓
- Article 36-51 ✓
- Taken From Ireland
- Committee: Tej Bahadur Supru
- No any Judicial power or hearing works over DPSP.
- Parliament & Executive has to work with DPSP. ✓

- पार्ट IV ✓
- आर्टिकल 36-51 ✓
- आयरलैंड से लिया गया
- कमेटी: तेज बहादुर सुप्रू
- DPSP पर कोई जूडिशियल पावर या हियरिंग काम नहीं करती।
- पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को DPSP के साथ काम करना होगा।

- Article 36: Definition/ राज्य की परिभाषा
- Article 37: Application of the DPSPs (non-justiciable but fundamental in governance) / राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अनुप्रयोग (अप्रतिवादी लेकिन शासन में मूलभूत)
- Article 38: State to secure a social order for the promotion of the welfare of the people
(कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा)
- Article 39: Certain principles of policy to be followed by the State
- Article 39A: Equal justice and free legal aid
(सामान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है)
- अनुच्छेद 39 (ख) सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके.
अनुच्छेद 39 (ग) धन का समान वितरण

V. Imp. Article 40: Organisation of village panchayats (ग्राम पंचायतों का संगठन)

- Article 41: Right to work, to education and to public assistance in certain cases (कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार)
- Article 42: Provision for just and humane conditions of work and maternity relief (काम की न्याय-संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध)
- Article 43: Living wage, etc., for workers (कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन)
- Article 43A: Participation of workers in management of industries
- Article 44: Uniform civil code for the citizen (नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता)
- Article 45: Provision for free and compulsory education for children

- Article 46: Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections (अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ-संबंधी हितों की अभिवृद्धि)
- Article 47: Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health (पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य)

Article 48: Organisation of agriculture and animal husbandry; prohibition of cow slaughter / कृषि और पशुपालन का संगठन; गौ-हत्या पर प्रतिबंध

Article 48A: Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife (पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा)

DPSP

- Article 49: Protection of monuments and places and objects of national importance (राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण)
- Article 50: Separation of judiciary from the executive (कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण)
- Article 51: Promotion of international peace and security (अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि)

अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं, जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं; जैसे:

Hindi

^(A)
अनुच्छेद 350 (क) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना
(Prime Education in Mother language)

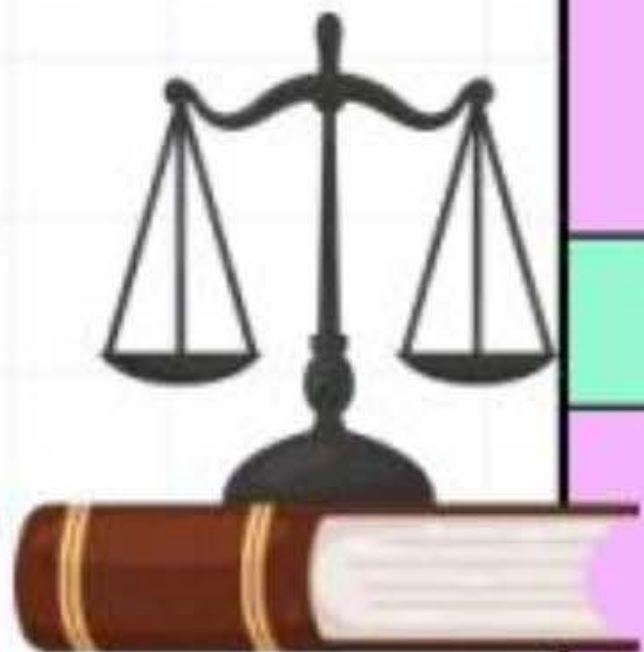
अनुच्छेद 351 हिंदी को प्रोत्साहन देना (Promotion of Hindi)

Art 32

Copied

Borrow

- The Directive Principles of State Policy are enumerated in Part IV of the Indian Constitution from Articles 36 to 51./ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 36 से 51 तक सूचीबद्ध किया गया है।
- The idea of DPSP is borrowed from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution./ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार 1937 के आइरिस संविधान से लिया गया है, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था।
- Dr. BR Ambedkar described these principles as 'novel features' of the Indian Constitution./ डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की 'नवीन विशेषताएँ' बताया। ✓
- Granville Austin described the DPSP and Fundamental rights as the 'conscience of the constitution'./ ग्रानविले ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को 'संविधान की अंतरात्मा' बताया। ✓
- Mentioned in the Government of India Act, 1935 as 'Instrument of Instructions'. / भारत सरकार अधिनियम, 1935 में 'निर्देशों के साधन' के रूप में उल्लेख किया गया है। ✓



Features of DPSP :



- **DPSPs are guidelines or principles given to the State to frame laws and policies./** नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को कानून और नीतियाँ बनाने के लिए दिए गए दिशानिर्देश या सिद्धांत हैं।
- **Aim to establish social and economic democracy./** सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य।
- **Non-justiciable but fundamental in governance/** न्यायोचित नहीं, लेकिन शासन में मौलिक
- **The directive Principles though non-justiciable in nature, but help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law./** निदेशक सिद्धांत यद्यपि न्यायोचित नहीं हैं, लेकिन ये न्यायालयों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जाँच और निर्धारण में सहायता करते हैं।

Objectives of DPSP :



- **To ensure social, economic, and political justice.**
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। ✓
- **To reduce inequality of income, status, and opportunities.**
आय, स्थिति और अवसरों की असमानता को कम करना। ✓
- **To promote welfare of the people.**
जन कल्याण को बढ़ावा देना। ✓
- **To provide the foundation for economic democracy.**

आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखना।

Classification of DPSP :

Socialistic Principles / समाजवादी सिद्धांत:

- **These principles reflect the ideology of socialism.** / ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को प्रतिबिम्बित करते हैं।
- **They lay down the framework of a democratic socialist state, aim at providing social and economic justice.** / ये एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है।

Articles : 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47



Gandhian Principles / गांधीवादी सिद्धांत:

- These principles are based on Gandhian ideology / ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं।
- They represent the program of reconstruction enunciated by Gandhi during national movement./ ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Articles: 40, 43, 43B, 46, 47, 48

Liberal- Intellectual Principles / उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत:

- These are inspired by liberal democracies of the West and aim to establish political and international justice./ ये पश्चिमी उदार लोकतंत्रों से प्रेरित हैं और इनका उद्देश्य राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय न्याय स्थापित करना है।

Articles : 44, 45, 48A, 49, 50, 51



Important Amendments in Directive Principles :

The 42nd Amendment Act of 1976 added four new Directive Principles to the Original list. / 42वें संशोधन अधिनियम ने मूल सूची में चार नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े।

- To secure opportunities for healthy development of children [Article 39(f)] / बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर सुनिश्चित करना [अनुच्छेद 39(f)]।
- To promote equal justice and to provide free legal aid to the poor [Article 39(A)] / समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना [अनुच्छेद 39(ए)]।
- To take steps to secure the participation of workers in the management of industries [Article 43(A)] / उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम
- To protect and improve the environment and to safeguard forests and wild life [Article 48(A)] / पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करना [अनुच्छेद 48(ए)]।



The 44th Amendment Act of 1978 added one more directive principle i.e. the state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities (Article 38) / 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने एक और नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा, अर्थात् राज्य अस्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करेगा (अनुच्छेद 38)।

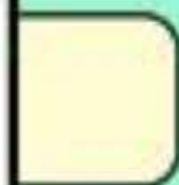
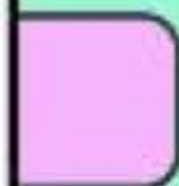
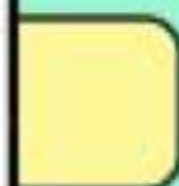


The 86th Amendment Act of 2002 changed the subject – matter of Article 45 and made elementary education a fundamental right under Article 21A. / 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 के विषय-वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21ए के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार बना दिया।

The 97th Amendment Act of 2011 added a new directive principle relating to co-operative societies. [Article 43(B)] / 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा [अनुच्छेद 43(B)]।

Difference Between Fundamental Rights and DPSP

Fundamental Rights	Directive Principles
1. These are negative as they prohibit the state from doing certain things	1. These are positive as they require the state to do certain things.
2. These are justiciable in nature	2. These are non-justiciable in nature
3. They aim at establishing political democracy in the country	3. They aim at establishing social and economic democracy in the country
4. They promote the welfare of the individual	4. They promote the welfare of the community. They are societarian and socialistic.
5. They do not require any legislation for their implementation	5. They require legislation for their implementation.
6. The courts are bound to declare a law violative of any of the fundamental Rights as unconstitutional and invalid	6. The courts cannot declare a law violative of any of the directive Principles as unconstitutional and invalid.
7. They have legal sanctions	7. They have moral and political sanctions.



मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच अंतर



मौलिक अधिकार	राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
1. ये नकारात्मक होते हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं।	1. ये सकारात्मक होते हैं क्योंकि ये राज्य को कुछ कार्य करने हेतु निर्देश देते हैं।
2. इनका स्वरूप न्यायालय में लागू करने योग्य (न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय) होता है।	2. इनका स्वरूप न्यायालय में लागू करने योग्य (अप्रवर्तनीय) होता है।
3. इनका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।	3. इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।
4. ये व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं।	4. ये समाज के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। ये समाजवादी और सामुदायिक प्रकृति के होते हैं।
5. इनके कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती।	5. इनके कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है।
6. न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर सकते हैं।	6. न्यायालय नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले किसी कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकते।
7. इन्हें कानूनी प्रतिबंध का समर्थन प्राप्त है।	7. इन्हें नैतिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त है।

Criticism of the Directive Principles

No legal force/ कोई कानूनी बल नहीं:

- The directive principles have been criticized mainly because of their **non-justiciable nature**. / निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना मुख्यतः उनके गैर-न्यायसंगत स्वभाव के कारण की गई है।
- **KC Wheare** called them as '**manifesto of aims and aspirations**'. / के.सी. व्हेयर ने इन्हें 'उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणापत्र' कहा है।
- **T.T. Krishnamachari** describes the directives as '**a veritable dustbin of sentiments**'. / टी.टी. कृष्णमाचारी ने निर्देशों को 'भावनाओं का वास्तविक कूड़ेदान' बताया है।
- **K.T. Shah** called them with '**a cheque on a bank, payable only when the resources of the bank permit**'. / के.टी. शाह ने इन्हें 'बैंक पर एक चेक के समान बताया है, जिसका भुगतान तभी किया जा सकता है जब बैंक के संसाधन अनुमति दें।'

टी.टी.
कृष्णमाचारी



के.टी. शाह

Illogically arranged / अतार्किक रूप से व्यवस्थित:

- **According to N. Srinivasan, 'the directives are neither properly classified nor logically arranged./** एन. श्रीनिवासन के अनुसार, 'निर्देशिकाएँ न तो उचित रूप से वर्गीकृत हैं और न ही तार्किक रूप से व्यवस्थित हैं।'
- **The declaration mixes up relatively unimportant issues with the most vital economic and social question./** यह घोषणापत्र अपेक्षाकृत महत्वहीन मुद्दों को सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों के साथ मिला देता है।

Constitutional conflicts / संवैधानिक संघर्ष:

- **K Santhanam has pointed out that the Directives lead to a constitutional conflicts/** के. सन्थानम ने बताया है कि ये निर्देशिकाएँ संवैधानिक संघर्षों को जन्म देती हैं।
- **Between the centre and the states/** केंद्र और राज्यों के बीच
- **Between the President and the Prime Minister/** राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच
- **Between the governor and the chief minister./** राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच।

Conservative in nature/ रूढ़िवादी प्रकृति:

- **According to Sir Ivor Jennings, the directives are based on the political philosophy of the 19th century England./** सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार, ये निर्देशिकाएँ 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं।